(ख) ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई ई । मेवाड़ चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, भीलवाड़ा द्वारा उठाये गये मुद्दों पर विचार किया जा रहा है और उन पर यथासमय उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

विवरण

(क) अभ्रक व्यापार निगम को राजस्थान के अभ्रक की खरीद नियमित रूप से अर्थात् लगभग एक महीने में एक बार करनी चाहिए ।

(ख) अभ्रक व्यापार निगम द्वारा राजस्थान से खरीदी जाने वाली मात्रा का मूल्य 86 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ।

(ग) अभ्रक व्यापार निगम को राजस्थान की अभ्रक को समर्थन कीमतों पर खरीदना चाहिए, प्रतियोगी आधार पर नहीं ।

(घ) खरीदारियां कुछ चुने हुए ग्रेडों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि सभी ग्रेडों का अभ्रक खरीदा जाना चाहिए ।

(ङ) अभ्रक व्यापार निगम द्वारा खरीदे जाने वाले अभ्रक का भुगतान भीलवाड़ा में किया जाना चाहिए, अभ्रक व्यापार निगम के प्रधान कार्यालय से नहीं ।

(च) अभ्रक व्यापार निगम को अपने भीलवाड़ा स्थित कार्यालय में उत्कृष्ट नमूने रखने चाहिए जिन्हें राजस्थान अभ्रक के भावी विक्रेता अपने-मार्गदर्शन के लिए उन्हें देख सकें ।

(छ) राजस्थान में अभ्रक पर आधारित उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए ।

(ज) अभ्रक व्यापार निगम को खरीदारों से प्राप्त क्रयादेशों के आधार पर राजस्थान से अभ्रक की पपड़ियों, स्क्रैप तथा पाउडर की खरीद करनी चाहिए ।

(झ) राजस्थान अभ्रक व्यापार तथा उद्योग का प्रतिनिधि अभ्रक सलाहकार समिति में नामित किया जाना चाहिए ।

Ceiling on Profit and expansion of Trade and Commerce

1566. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to enact a suitable legislation to equate land ceiling with the profit and expansion of trade and Commerce;

(b) whether Government views this curtailment of income from land and the profits from trade, commerce and industry as a discrimination; and

(c) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). Ceilings on land were imposed with a view to reducing disparities in incomes and wealth in the rural sector. The same objective is sought to be achieved in the non-agricultural sector through the taxation of income and wealth.

Shifting of Surplus Labour to Iural Industrial Cooperatives

1567. SHRI S. D. SOMASUNDARAM: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state whether Government propose to bring about basically a small peasant economy integrated through production and marketing cooperatives and gradual shifting of surplus labour to rural industrial cooperatives?